*भारत का विदेशी व्यापार: 2014-15 (अप्रैल-सितंबर)**

इस आलेख में वाणिज्यिक आसूचना और अंकसंकलन महानिदेशालय (डीजीसीआई*एण्डएस) द्वारा जारी की* गई आधार-सामग्री के आधार पर अप्रैल-सितंबर *2014 के दौरान भारत के पण्य व्यापार कार्यनिष्पादन* की समीक्षा की गई है। इस अवधि के दौरान भिन्न-भिन्न पण्य-वार और दिशा-वार ब्यौरे का भी इसमें विश्लेषण किया गया है।

मुख्य-मुख्य विशेषताएँ

2013-14 के निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी होने के कारण 2014-15 की पहली तिमाही के दौरान भारत के व्यापार कार्यनिष्पादन में काफी सुधार हुआ है। तथापि, 2014-15 की दूसरी तिमाही में प्रमुख व्यापार साझीदार अर्थव्यवस्थाओं में कम गतिविधियों के होने और घरेलू स्तर पर कतिपय निर्यात करने वाले उद्योगों/क्षेत्रों में आपूर्ति पक्ष में अड़चनें बनी रहने के कारण निर्यात वृद्धि धीमी पड़ गई। इसके साथ-साथ, आयात, विशेष रूप से तेल से इतर गैर सोने में तेजी से वृद्धि हुई, पूर्व अनुभव से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के भीतर कतिपय क्षेत्रों में उत्पादन में आयी कमी को आयात के जरिए पूरा किया जा रहा है।

I. भारत का पण्य व्यापार (अप्रैल-सितंबर 2014)

निर्यात

मई-जुलाई 2014 के दौरान निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि उत्तरवर्ती महीनों में आयी गिरावट की तुलना में कहीं अधिक थी। दूसरी तिमाही में निर्यात में वृद्धि अच्छी न होने के बावजूद अप्रैल-सितंबर 2014 के दौरान निर्यात में समग्र वृद्धि अप्रैल-सितंबर 2013 के 6.3 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो गई (चार्ट 1 और सारणी 1)।

पण्य-वार और गंतव्य-वार निर्यात

भले ही, अप्रैल-सितंबर 2014 के दौरान निर्यात में हुई वृद्धि अप्रैल-सितंबर 2013 की तुलना में अधिक रही हो, किंतु यह वृद्धि कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित थी। वृद्धि मुख्यतः चार क्षेत्रों अर्थात इंजीनियरी वस्तुओं, पेट्रोलियम उत्पादों, रेडीमेड कपड़ों और मूलभूत रसायनों और फर्मास्यूटिकल्स में हुई थी जिनका निर्यात के कुल मूल्य में 58 प्रतिशत हिस्सा था। अन्य क्षेत्र अर्थात रत्न और

चार्ट 1 : भारत के व्यापार की मासिक प्रवृत्ति

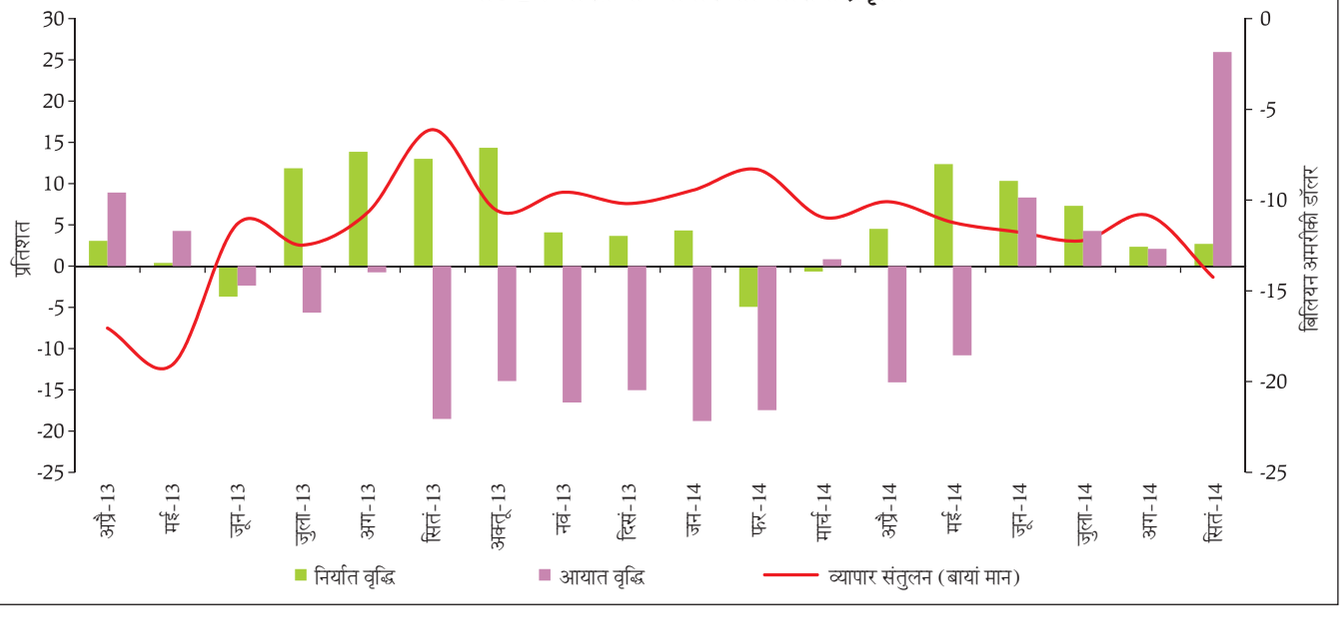

* आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्त प्रभाग में तैयार किया गया। आलेख का पिछला लेख भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, अक्तूबर 2014 अंक में प्रकाशित किया गया।

सारणी 1 : भारत का पण्य व्यापार

(बिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद		अप्रैल-जून	
		2013-14 सं	2014-15 अ
निर्यात		**153.8 (6.3)**	**163.7 (6.5)**
जिनमें से :	तेल	32.7 (19.0)	32.9 (0.8)
	तेल से इतर	121.1 (3.3)	130.8 (8.0)
	स्वर्ण	4.6 (-56.5)	5.2 (11.8)
तेल से इतर स्वर्ण से इतर		116.4 (9.3)	125.6 (7.9)
आयात		**230.5 (-2.5)**	**234.1 (1.6)**
जिनमें से :	तेल	80.0 (0.0)	82.4 (2.9)
	तेल से इतर	150.5 (-3.8)	151.7 (0.8)
	स्वर्ण	20.2 (-0.2)	14.7 (-27.3)
तेल से इतर स्वर्ण से इतर		130.3 (-4.4)	137.1 (5.2)
व्यापार घाटा		-76.7	-70.4
जिनमें से :	तेल	-47.3	-49.4
	तेल से इतर	-29.4	-21.0
तेल से इतर स्वर्ण से इतर		-13.9	-11.5

सं : संशोधित; अ: अनंतिम।

टिप्पणी: कोष्टक में दर्शाये गए आंकड़े वृद्धि दर के है।

स्रोत : डीजीसीआईएण्डएस

आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, आयल मिल्स और लौह अयस्क में गिरावट आई (चार्ट 2 और 3)।

वैश्विक मांग की स्थितियों के व्यापक प्रभाव के बावजूद, कतिपय क्षेत्रों के निर्यात में क्षेत्र-विशेष मुद्दों के साथ-साथ घरेलू स्तर पर और गंतव्य देशों में किए गए नीतिगत परिवर्तन का प्रभाव देखा गया। उदाहरण के लिए, इंजिनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में हुई वृद्धि नए बाजारों में किए गए निर्यात का परिणाम है। इस अवधि के दौरान श्रीलंका इंजिनियरिंग वस्तुओं के लिए प्रमुख निर्यात गंतव्य स्थान के रूप में उभरा है। वैश्विक स्तर पर चल रही मंदी के दौर में, विशेष रूप से ईयू बाजारों में, इस परिवर्तन से भारतीय कंपनियों को मदद मिली है। इसी तरह, भारतीय कंपनियों द्वारा बढ़ती श्रम लागत का लाभ उठाकर रेडीमेड वस्त्रों का निर्यात अन्य उभरती बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थों जैसे चीन, बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया की तुलना में अधिक किया गया, उनमें से कई (उदाहरण के लिए, बांग्लादेश और चीन) देश श्रम की कमी और सख्त घरेलू श्रम कानून से जूझ से रहे हैं।

दूसरी तरफ, कमजोर बाह्य मांग की स्थितियों और घरेलू क्षेत्र-विशेष की अड़चनों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय कीमतों में कमी के चलते कतिपय क्षेत्रों में निर्यात वृद्धि प्रभावित हुई है। सूती धागे के निर्यात में आयी गिरावट का कारण अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट और चीन से मांग कम होना था। अप्रैल 2014 से लागू चीन की नई कॉटन संबंधी नीति के चलते चीन के मिलों को घरेलू बाजार से सस्ती दर पर धागे मिलने लगे जिससे अंततराष्ट्रीय

चार्ट 2 : प्रमुख क्षेत्रों में निर्यात वृद्धि: अप्रैल-सितंबर 2014

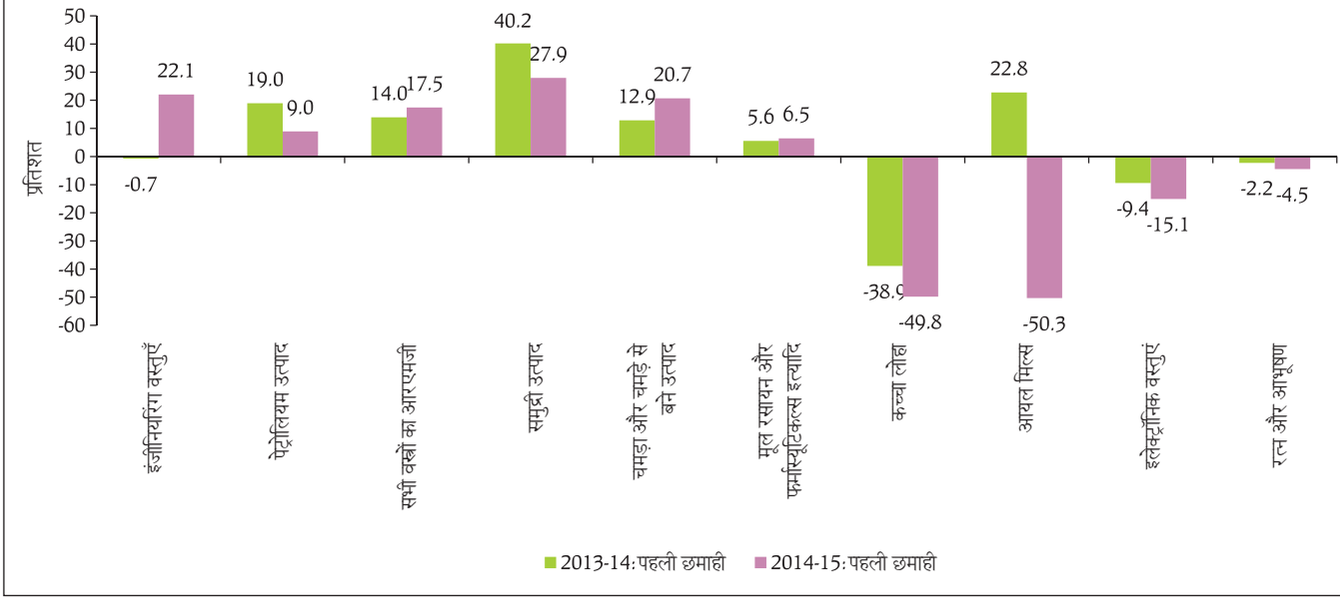

चार्ट 3 : अप्रैल-सितंबर 2014 में निर्यात वृद्धि में क्षेत्रवार भारित योगदान

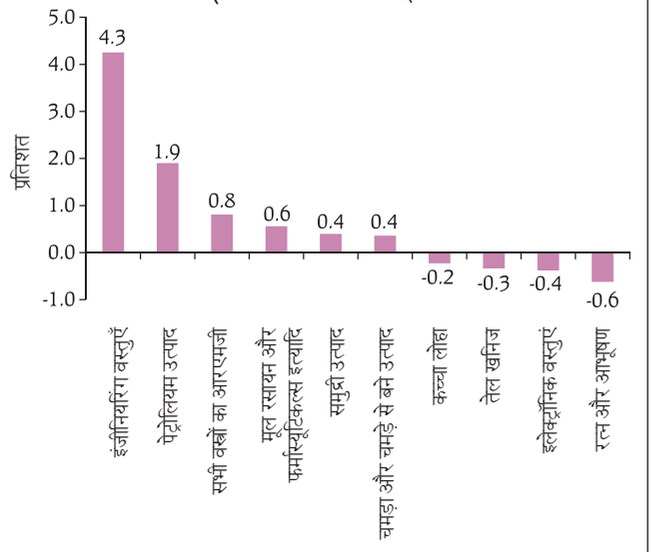

चार्ट 4 : चुनिंदा देशों के निर्यात में वृद्धि

कीमतों में गिरावट आई और वैश्विक मांग भी कम पड़ गई। इस नई नीति ने स्थानीय उत्पादकों (जिन्होंने ने चीन में सूत और सूती धागे की बढ़ी घरेलू कीमतों को सामना किया जिसमें अन्य देशों से धागा आयात करने वाले टेक्टाइल मिल्स भी शामिल हैं) को बढ़ावा देने के लिए घरेलू कॉटन को जमा करने के चीन के तीन वर्ष के कार्यक्रम में समाप्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में चीनी प्राधिकारियों ने यह निर्णय लिया है कि अतिरिक्त आयात कोटा (विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) प्रवेश प्रतिबद्धता को छोड़कर) न जारी किया जाए, ताकि घरेलू टेक्सटाइल कंपनियां चीनी में ही बने धागे का अधिक से अधिक उपयोग करे। हाल के महीनों में तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आयी तेज गिरावट के चलते पेट्रोलियम उत्पादों, जो अप्रैल-सितंबर 2014 में कुल निर्यात का लगभग 22 प्रतिशत हिस्सा था, के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। खनन गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटाने के बावजूद लोहे का निर्यात घरेलू आपूर्ति पक्ष के चलते कम रहा। निर्यात कर और लौह अयस्क पर लगाए गए रेल किराया भाड़ा ने न केवल निर्यात को कम किया, बल्कि घरेलू स्टील कंपनियों, जो दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और बाज़ील से आयात कर अपनी जरूरतों को पूरा करती हैं, को भी प्रभावित किया है। इसी प्रकार, लगता है कि ऑयल मिल्स का निर्यात भी प्रत्याशित सोयबिन उत्पादन, जिसके चलते स्थानीय बाजार में सोयाबिन की लागत बढ़ी हैं, की तुलना में कम होने से प्रभावित हुआ है।

गंतव्य-वार निर्यात विश्लेषण से यह पता चलता है कि अप्रैल-दिसंबर 2014 के दौरान वर्ष-दर-वर्ष आधार पर यूएस, यूएई, चीन और दक्षिण कोरिया को किए गए निर्यात में वृद्धि हुई है। तथापि, साउदी अरेबिया, हांगकांग, सिंगापुर और यूरोपीय संघ के देशों (जर्मनी को छोड़कर) में किया गया निर्यात या तो कम हुआ है या फिर नकारात्मक रहा है (चार्ट 4)। इन प्रमुख व्यापारिक साझीदार देशों में कमजोर मांग स्थितियों के चलते भारत के निर्यात के बारे में चिंता बढ़ा दी है।

कुल निर्यात में हिस्से के तौर पर भारतीय वस्तुओं के लिए अमेरिका सर्वोच्च गंतव्य के रूप में बना रहा, जिसका हिस्सा 13.8 प्रतिशत है, उसके बाद यूएई (10.5 प्रतिशत), साउदी अरेबिया (4.4 प्रतिशत), हांगकांग (4.2 प्रतिशत) और चीन (3.7 प्रतिशत) में रहा। रत्न और आभूषण के निर्यात में कमी के बावजूद, यूएस को किए गए निर्यात में वृद्धि मुख्यतः औषधि, समुद्री उत्पाद और लोहा और स्टील उत्पाद के चलते हुई। जैसा कि यूरोपीय संघ के अधिकांश देशों में देखा गया कि निर्यात या तो कम रहा है या फिर नकारात्मक रहा है, वैसे ही भारत के निर्यात में ईयू को गिए गए निर्यात के हिस्से में मामूली गिरावट आई है (सारणी 3)।

सारणी 2: प्रधान क्षेत्रों में भारत का निर्यात

(प्रतिशत अंश)

क्षेत्र/देश		2012-13	2013-14	2013-14	2014-15
		अप्रैल-मार्च		अप्रैल-सितंबर	
I.	**ओईसीडी देश**	**34.2**	**34.6**	**34.8**	**35.0**
	यूरोपीय संघ	16.8	16.5	16.2	15.6
	उत्तरी अमेरिका	12.7	13.1	13.6	14.4
	जिसमें से: अमेरिका	12.0	12.4	12.9	13.8
	एशिया और ओशनिया	2.9	3.0	3.0	2.8
	अन्य ओईसीडी देस	1.8	2.1	2.0	2.2
II.	**ओपीईसी**	**20.9**	**19.3**	**19.7**	**20.2**
III.	**पूर्वी यूरोप**	**1.3**	**1.2**	1.2	1.1
IV.	**विकासशील देश**	**41.6**	**41.3**	**39.6**	**42.6**
	एशिया	28.7	28.9	28.3	27.9
	सार्क	5.0	5.6	5.0	6.4
	अन्य एशियाई विकासशील देश	23.6	23.3	23.3	21.5
	चीनी जनतांत्रिक गणतंत्र	4.5	4.8	3.8	3.7
	अफ्रीका	8.1	8.4	7.8	9.7
	लैटीन अमरीका	4.9	4.0	3.5	5.1
V.	**अन्य /अविनिर्दिष्ट**	1.9	3.7	4.7	1.1
	कुल निर्यात	**100**	**100**	**100**	**100**

स्रोत : डीजीसीआईएण्डएस डेटा से संकलित

विभिन्न क्षेत्रों के निर्यात संबंधी मुद्दों को महत्व देते हुए सरकार द्वारा यूनियन बजट 2014-15 में अनेक उपायों की घोषणा की गई (बॉक्स)।

आयात

लगातार बारह महीनों की गिरावट के बाद जून 2014 से भारत के आयात में वृद्धि शुरू हुई। परिणामस्वरूप अप्रैल-सितंबर 2014 के दौरान भारत का आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि के 2.5 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 1.6 प्रतिशत बढ़ा है।

पण्य-वार और गंतव्य-वार आयात

पण्य-वार आंकड़े यह दर्शाते हैं कि अप्रैल-सितंबर 2014 के दौरान प्रधान पण्यों में पीओएल आयात जो कुल आयात का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा है, में बढ़ोतरी है। यद्यपि, अप्रैल-जुलाई 2014 (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर) के दौरान कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें उच्च बनी रहीं, किंतु बाद में कीमतें कम होने से पीओएल आयात वृद्धि को कम किया जा सका (सारणी 4)।

बॉक्स : भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित हाल में किए गए नीतिगत उपाय

भारत के व्यापार को बढ़ावा देने क लिए यूनियन बजट 2014-15 में अनेक उपाय प्रस्तावित हैं, जिन्हें नीचे दिया जा रहा है:

- बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में राज्यों की सक्रिय भूमिका और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पूरी सहूलियत देने को महत्व देते हुए सरकार ने निर्यात संवर्धन मिशन का प्रस्ताव किया है ताकि सभी हितधारकों को एक समूह में लाया जा सके।
- रेडीमेड कपड़ों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कतरन, अलंकरण और अन्य ब्योरेवार मदों के आयात के लिए शुल्क मुक्त पात्रता को उनके निर्यात मूल्य का 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।
- निम्नलिखित मदों पर मूल सीमा शुल्क में छूट प्रदान की गई:
- फैटी एसिड, क्रूड पाम स्टेरीन, आरबीडी (रिफाइन्ड ब्लीज्ड डीओडराइज्ड) और अन्य पाम स्टेरीन, साबुन और ओलियोकेमिकल्स के विनिर्माण के लिए विर्निदिष्ट औद्योगिक ग्रेड कच्चा तेल 7.5 प्रतिशत से शून्य ;
- कच्ची ग्लीसरीन 12.5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत और साबुन बनाने में कच्ची ग्लीसरीन का इस्तेमाल 12.5 प्रतिशत से शून्य;
- स्टील ग्रेड लाइमस्टोन और स्टील ग्रेड डोलोमाइट 5 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत;
- बैटरी वेस्ट और बैटरी स्कैप 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत;
- कोल तार पिच 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत
- स्पैंडेक्स धागे बनाने के लिए विनिर्दिष्ट इनपुट 5 प्रतिशत से शून्य
- केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स में नया निवेश और क्षमता बढ़ाने को प्रोत्साहित करने के लिए मूल सीमा शुल्क को निम्नलिखित मदों के लिए आयात के लिए घटा दिया गया;
- रिफार्मेट 10 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत;
- एथेन, प्रोपेन, एथलीन, प्रोपीलीन, बुटाडाइन और अर्थो-जीलीन 5 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत;
- मेथाइल एलकोहल और डीनेचर्ड एथाइल एलकोहल 7.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत;
- क्रूड नैप्थलीन 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत;
- दुरुपयोग रोकने और मूल्यांकन विवाद से बचने के लिए अर्ध-संसाधित, अधे कटे अथवा टूटे डायमंड, कट और पॉलिस वाले डायमंड और रंगीन जेमस्टोन पर मूल सीमा शुल्क को संगत बनाने के लिए 2.5 प्रतिशत का प्रस्ताव किया गया है।

(क्रमशः)

- निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहुमूल्य और कम बहुमूल्य स्टोन के प्री-फार्म को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है।
- घरेलू इलेक्ट्रानिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित का भी प्रस्ताव किया गया है: (i) ऐसे विर्निदिष्ट टेलीकाम उत्पादों पर 10 प्रतिशत का मूल सीमा शुल्क लगाया जाय जो कि सूचना प्रौद्योगिकी करार के अंतर्गत नहीं आता है, (ii) 4 प्रतिशत के विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) से व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाने में इस्तेमाल सभी इनपुट और घटकों को छूट, (iii) घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुएं और आयातित वस्तओं के बीच समानता प्रदान करने के लिए आयातित इलेक्ट्रानिक उत्पादों पर शिक्षा उपकर लगाना, (iv) स्मार्ट कार्ड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले पीवीसी शीट और रिबन पर 4 प्रतिशत एसएडी की छूट।
- घरेलू स्टेनलेस स्टील को बढ़ावा देने के लिए स्टेनलेस स्टील के आयातित फ्लैट-रोल्ड उत्पादों पर मूल सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से बढ़कर 7.5 प्रतिशत किया गया।
- ईवीए (एथलीन) शीट और बैक शीट बनाने में इस्तेमाल के लिए सौर ऊर्जा, विनिर्दिष्ट इनपुट का अधिकतम उपयोग करने के लिए; पीवी रिबन बनाने के लिए फ्लैट कॉपर वायर में मूल सीमा शुल्क में छूट प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, 5 प्रतिशत की रियायती मूल सीमा शुल्क सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए जरुरी मशीनरी और उपस्कर के लिए प्रदान की गई।
- विंड आपरेटेड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर की बियरिंग बनाने में इस्तेमाल होने वाले फार्ज्ड स्टील रिंग पर मूल सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
- विंड आपरेटेड जनरेटर बनाने में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों और कच्ची सामग्री के निर्यात के लिए 4 प्रतिशत के एसएडी की छूट प्रदान की गई है।
- कंप्रेस्ड बोयोगैस संयत्र (बोयो-सीएनजी) स्थापित करने के लिए जरुरी मशीनरी और उपकरण पर रियायती मूल सीमा शुल्क 5 प्रतिशत निर्धारित की गई।
- घरेलू प्राकृतिक स्त्रोतों को सुरक्षित रखने के लिए बजट में बक्साइट पर निर्यात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।

  उपर्युक्त के अतिरिक्त, अनेकक्षेत्रों में आयात के लिए मूल सीमा शुल्क को संगत बनाने का प्रस्ताव किया गया है।
- रिज़र्व बैंक ने 21 मई 2014 को नामित बैंकों/एजेन्सियों/प्रतिष्ठानों द्वारा आयात किए जाने वाले सोने से संबंधित दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। संशोधित दिशनिर्देशों के अनुसार, विश्व व्यापार महानिदेशालय द्वारा नामित एजेन्सियों के रूप में पंजीकृत स्टार ट्रेडिंग/प्रीमियर ट्रेडिंग हाउसेस (एसटीएच/पीटीएच) को कतिपय स्थितियों के अधीन 20:80 योजना के तहत सोना आयात करने की अनुमति प्रदान की गई।

सारणी 3: कच्चे तेल की कीमतों की प्रवृत्तियां

(अमेरिकी डॉलर/बैरल)

अवधि	दुबई	ब्रेन्ट	डब्ल्यूटीआई*	भारतीय समूह**
1	2	3	4	5
2005-06	53.4	58	59.9	55.7
2006-07	60.9	64.4	64.7	62.4
2007-08	77.3	82.3	82.3	79.5
2008-09	82.1	84.7	85.8	82.7
2009-10	69.6	69.8	70.6	69.6
2010-11	84.2	86.7	83.2	85.1
2011-12	110	114.4	97.3	111.9
2012-13	106.9	110.5	92	108
2013-14	104.5	107.6	99.04	105.5
2014-15 छ1	103.7	106.1	100.4	104.4

*वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट

**कच्चे तेल के भारतीय समूह की संरचना खट्टे ग्रेडों के लिए ओमन और दुबई तथा मीठे ग्रेड के लिए ब्रेन्ट के औसत को 2013-14 के लिए 72.04 : 27.96 अनुपात में द्योतित करती है।

स्रोत : अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सांख्यकीय, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मानिटर डाटा-पण्य (विश्व बैंक) और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार

मात्रा के संबंध में, पीओएल आयात में मामूली वृद्धि देखी गई। यद्यपि, दूसरी तिमाही में सोने के आयात में तेज वृद्धि देखी गई किंतु 2014-15 की पहली छमाही में सोने का कुल आयात पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कम बना रहा। मात्रा के संबंध में अप्रैल-सितंबर 2014 के दौरान सोना आयात 365 टन रहा जो अप्रैल-सितंबर 2013 के स्तर से 20 प्रतिशत कम है।

भले ही, तेल से इतर गैर स्वर्ण आयात में वृद्धि घरेलू अर्थव्यवस्था में उतरोत्तर सुधार को दर्शाती हो किंतु कतिपय क्षेत्रों में आपूर्ति पक्ष अड़चनों ने भी आयात के जरिए भरपाई करने के लिए प्रेरित किया है। विशेष रूप से, अप्रैल-सितंबर 2014 के दौरान बुनियादी और अर्धनिर्मित वस्तुएं जिसमें लोहा और इस्पात, गैर लौह धातुएं, धातु वाले अयस्क और अन्य खनिज, कृत्रिम रेजिन्स, प्लास्टिक सामग्री और इलेक्ट्रानिक घटक शामिल हैं, में तेज वृद्धि देखी गई। लोहे और इस्पात का अधिक आयात भी घरेलू

चार्ट 5: अप्रैल-सितंबर 2014 में प्रमुख मदों के आयात में वृद्धि

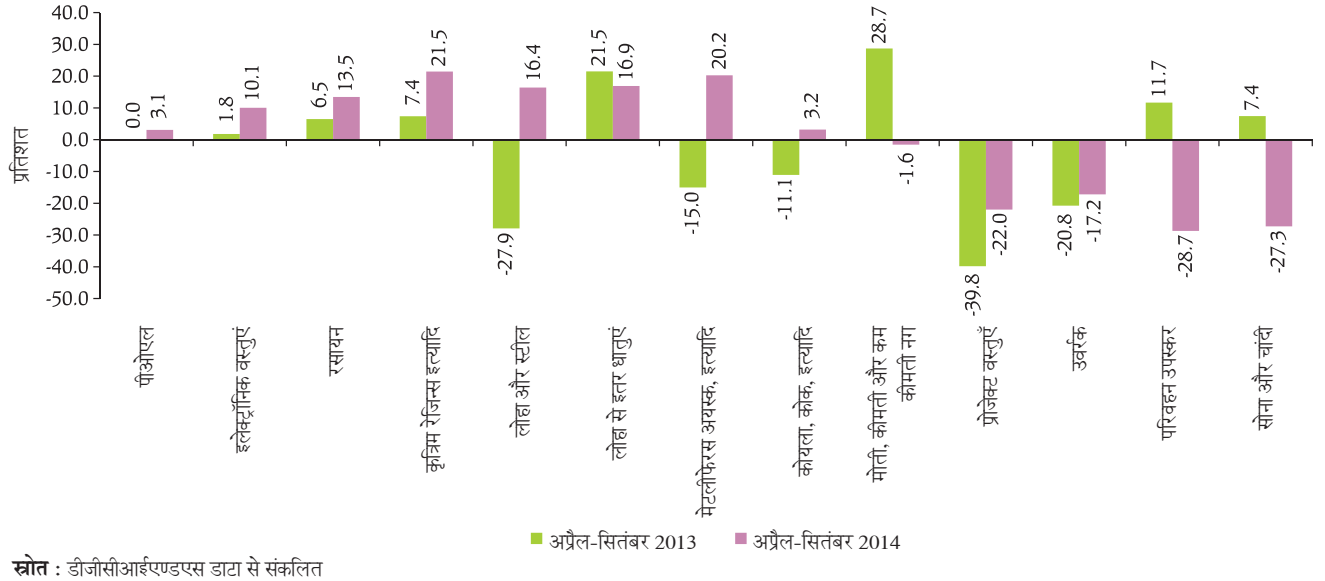

स्रोत : डीजीसीआईएण्डएस डाटा से संकलित

निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र में सुधार होने का संकेत हो सकता है। दूसरी तरफ, भारत का कोयला आयात अधिकांशतः कोल ब्लॉक आंबटन पर नियम-कानून और थर्मल आधारित विद्युत परियोजनाओं की बढ़ती जरुरतों के चलते घरेलू आपूर्ति पक्ष की अड़चनों को दर्शाता है। इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के आयात में बढ़ोतरी सीमा शुल्क संरचना में की गई कमी के चलते हैं क्योंकि कतिपय रेडीमेड इलेक्टानिक वस्तुओं पर उसके घटकों और कच्ची सामग्री की तुलना में कम सीमा शुल्क है। इसी वजह से कंपनियों ने घरेलू स्तर पर तैयार करने के बजाय रेडीमेड वस्तुओं को आयात किया है। इसके विपरीत, पूंजीगत वस्तुओं (अर्थात मशीन, उपकरण, मशीनरी, परियोजना वस्तुएं और परिवहन उपस्कर) का घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ने से इनके आयात या तो स्थिर रहा या फिर इसमें गिरावट आई। समग्र स्तर पर, अप्रैल-सितंबर 2014 के दौरान आयात वृद्धि में मुख्य योगदान पीओएल, वनस्पति तेल, इलेक्ट्रानिक वस्तुओं, रसायन, कृत्रिम रेजिन्स और लोहे और इस्पात का रहा है (चार्ट 5 और 6)।

व्यापार की दिशा से पता चलता है कि यूरोपीय संघ, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इराक, कुवैत, साउदी अरेबिया और यूएई से किए गए आयात में गिरावट आई है। तेल का निर्यात करने वाले देशों से आयात में तीव्र गिरावट का कारण अगस्त-सितंबर 2014 के दौरान तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आना है। स्विट्जरलैंड से किए गए आयात में 17.1 प्रतिशत की कमी का मुख्य कारण सोने का आयात कम होना है। इसके विपरीत, चीन से किए गए सोने के आयात में अप्रैल-सितंबर 2013 के 3.7 प्रतिशत की तुलना में 14.5 प्रतिशत रहा, जिसका मुख्य कारण टेलीकॉम घटकों के आयात में वृद्धि होना है, जो भारत के लिए सबसे बड़ा

चार्ट 6: अप्रैल-सितंबर 2014 में आयात वृद्धि में प्रमुख मदों का भारित योगदान

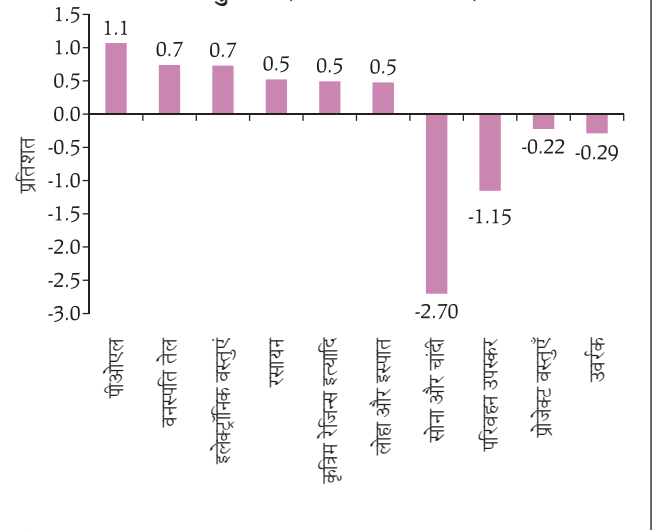

स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस डाटा से संकलित

सारणी 7 : भारत के आयातों में समूहों / देशों का हिस्सा

(प्रतिशत शेयर)

क्षेत्र / देश	2012-13	2013-14	2013-14	2014-15
	अप्रैल-मार्च		अप्रैल-सितंबर	
I. ओईसीडी देश	**28.8**	**25.6**	**27.2**	**24.9**
यूरोपीय संघ	10.6	11.1	11.1	10.6
फ्रांस	0.9	0.8	0.8	0.8
जर्मनी	2.9	2.9	2.8	2.7
यूके	1.3	1.3	1.6	0.9
उत्तरी अमेरिका	5.7	5.7	6.1	5.2
अमेरिका	5.1	5.0	5.4	4.5
एशिया और ओशनिया	5.3	4.4	4.5	4.3
अन्य ओईसीडी देश	7.1	4.5	5.5	4.8
स्विट्ज़रलैंड	6.5	4.1	5.3	4.3
II. ओपीईसी	**38.3**	**39.4**	**38.9**	**37.1**
III. पूर्वी यूरोप	**1.6**	**1.7**	**1.6**	**1.9**
IV. विकासशील देश	**30.8**	**32.0**	**31.5**	**34.4**
एशिया	23.5	24.8	24.8	26.2
सार्क	0.5	0.6	0.5	0.6
अन्य एशियाई विकासशील देश	23.0	24.2	24.3	25.6
जिनमें से :				
चीनी जनतांत्रिक गणतंत्र	10.7	11.4	11.2	12.7
अफ्रीका	3.9	3.3	3.6	4.4
लातीन अमेरिका	3.4	3.9	0.5	0.2
V. अन्य / अविनिर्दिष्ट	**0.5**	**1.3**	**0.9**	**1.7**
कुल आयात	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत : डीजीसीआईएण्डएस डेटा से संकलित

स्रोत देश बन गया उसके बाद साउदी अरेबिया, यूएई, यूएस और स्विट्ज़रलैंड का क्रम आता है (सारणी 7)।

व्यापार घाटा

आयात में वृद्धि होने के बावजूद भारत का व्यापार घाटा अप्रैल-सितंबर 2014 में 2013-14 की समान अवधि की तुलना में कम हुआ है जो निर्यात में हुए सुधार को दर्शाता है।

II. वैश्विक व्यापार परिदृश्य

2014 में विश्व वृद्धि 3.3 प्रतिशत के साथ स्थिर बने रहने के अनुमान के चलते 2014 की पहली छमाही में सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गतिविधियां प्रत्याशित गति की तुलना में धीमी गति से बढ़ीं। विशेष रूप से, उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में वृद्धि लगभग अवरुद्ध बनी रही (चार्ट 7)। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार ईएमडीई के आयात की मात्रा में वृद्धि 2013 के 4.7

चार्ट 7 : विश्व आर्थिक वृद्धि

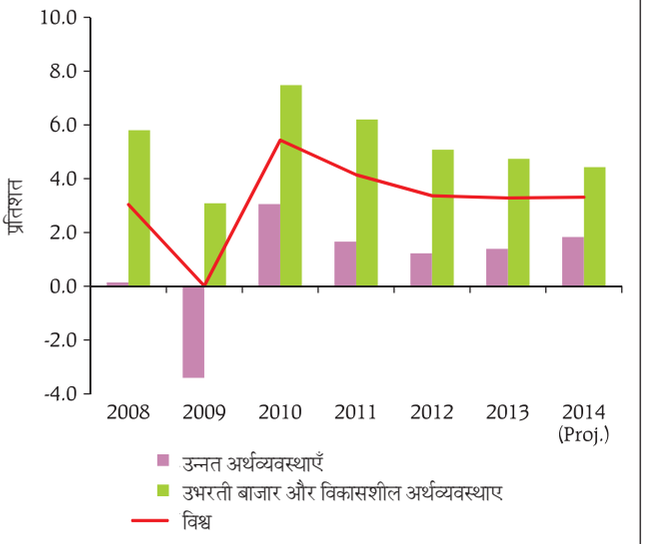

स्रोत : विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अक्तूबर 2014

प्रतिशत से घटकर 2014 में 4.4 प्रतिशत रह जाएगी। तथापि, विश्व व्यापार की मात्रा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से आयात के चलते अधिक रहने की संभावना है।

2014 में मुख्य पण्य कीमतों में अभी तक कमी आई है (चार्ट 9)। भले ही, भौगोलिक तनावों बढ़ने से 2014 के मध्य में कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर अस्थाई उर्ध्वगामी दबाव रहा हो, किंतु हाल में आयी गिरावट अमरीकी डॉलर के मजबूत होने,

चार्ट 8: वस्तुओं के निर्यात मात्रा में वृद्धि

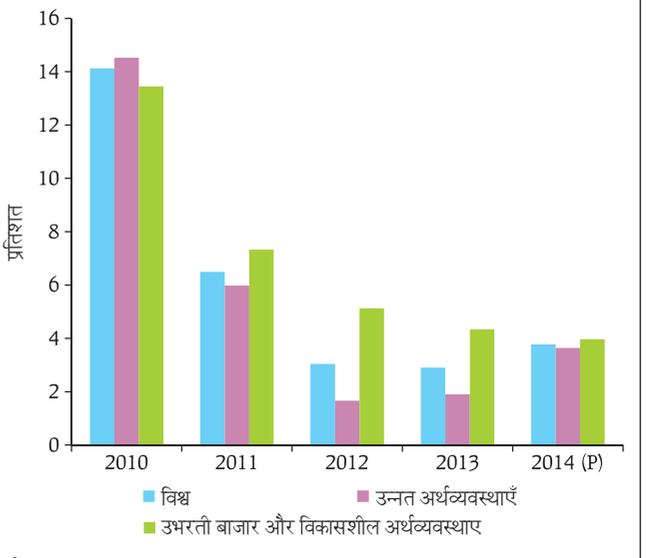

स्रोत : अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सांख्यकीय, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष

चार्ट 9: विश्व पण्य कीमतें

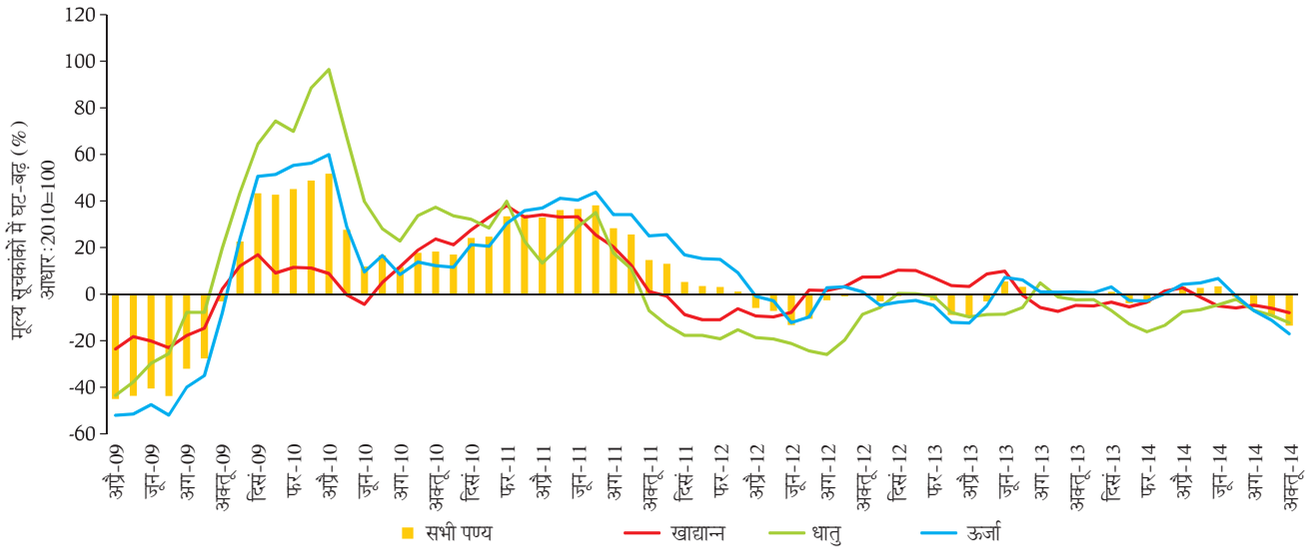

स्रोत : अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सांख्यकीय, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष

ओपेक और गैर ओपेक देशों के दोनों संगठनों द्वारा बढ़ी आपूर्ति और प्रमुख इएमडीई और यूरो क्षेत्र की कमजोर मांग को दर्शाती है। यूएस ऊर्जा सूचना प्रबंध, सितंबर 2014 के अनुसार यह रिफाइनरी चलाने में मौसमी कमी के चलते मांग में कमी के प्रभाव और साउदी अरेबिया से कच्चे तेल के आयात में मौसमी वृद्धि का भी दर्शाती है। इसी प्रकार, धातुओं की कीमतें 2014 में अब तक कम हुई हैं। विशेष रूप से लौह अयस्क की अंतरराष्ट्रीय कीमतें 2014 में कम हुई जो कम लागत वाली आपूर्ति विशेष रूप से आस्ट्रेलिया और ब्राजील की अधिक मांग और चीन की कम मांग को दर्शाता है। वैश्विक आपूर्ति स्थिति में मौसम प्रेरित सुधार के चलते खाद्य कीमतों में गिरावट आयी है। इसके अतिरिक्त, मुख्य पण्यों की कीमतें कमजोर वैश्विक संभावना के चलते कम होने की संभावना है।

III. संभावना

अप्रैल-सिंतबर 2014 में भारत का व्यापार घाटा कम होने से भारत की समग्र भुगतान संतुलन के लिए सुखद स्थिति है। तथापि, हाल के महीनों में निर्यात वृद्धि में आई गिरावट ने एक विषम अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिवेश में डाउनसाइड जोखिम को बढ़ा दिया है। आयात पक्ष के संबधं में, मुख्य पण्यों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में कमी आने से आयात के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। यद्यपि, सोने का आयात बढ़ने से यह लाभ बराबर हो सकता है और समग्र आयात के मुख्य निर्धारकों का विस्तार हो सकता है। इसके अतिरिक्त, मई 2014 से तेल से इतर और गैर स्वर्ण आयात बढ़ सकता है, क्योंकि घरेलू गतिविधियां बढ़ सकती हैं।